भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2558
10.08.2026 को उत्तर देने के लिए

अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन

2558. श्री प्रदीप कुमार वर्मा:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा प्रमुख अवसंरचना एवं सार्वजनिक निवेश परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी तथा उनके समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक समेकित निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस तंत्र के अंतर्गत वर्तमान में निगरानी की जा रही परियोजनाओं की संख्या तथा कुल अनुमानित निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निगरानी व्यवस्था के परिणामस्वरूप परियोजनाओं के कार्यान्वयन में होने वाले विलंब तथा लागत वृद्धि को कम करने में सहायता मिली है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) को 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली चल रही केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं की स्थिति की निगरानी और ऑनलाइन पोर्टल/वेब निगरानी प्रणाली "परियोजना मूल्यांकन अवसंरचना निगरानी और राष्ट्रीय निर्माण हेतु विश्लेषण (पैमाना)" के माध्यम से करने का अधिदेश दिया गया है। सभी संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यान्वयन एजेंसियाँ एपीआई (ऐप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) और डेटा एंट्री मोड के माध्यम से पैमाना पोर्टल पर परियोजनाओं की जानकारी नियमित रूप से अपडेट करती हैं।

(ख): जून 2026 तक, एमओएसपीआई देश भर में चल रही 1,847 परियोजनाओं (जो पैमाना पोर्टल पर दर्ज हैं) की स्थिति की निगरानी करता है, जिन्हें 17 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जिनकी मूल लागत रू 35.61 लाख करोड़ और संचयी व्यय रू 21.96 लाख करोड़ है। तद्नुसार, इस मंत्रालय द्वारा सभी चल रही अवसंरचना परियोजनाओं का परियोजना -वार विवरण https:/paimana-proj.mospi.gov.in/ReportPage वेबसाइट पर प्रकाशित 'फ्लैश रिपोर्ट' में उपलब्ध है।

(ग) से (घ) : सभी हितधारकों (अवसंरचना संबंधी मंत्रालय/विभाग) को पैमाना पर उपलब्ध डेटा विश्लेषण के आधार पर उनकी परियोजना की स्थिति और उसमें हुए विलंब के संबंध में नियमित रूप से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे अपनी ओर से परियोजना कार्यान्वयन के प्रबंधन में आवश्यक हस्तक्षेप कर सकें। इसके अतिरिक्त, मासिक समीक्षा बैठकों और अन्य संचार माध्यमों से हितधारकों के साथ नियमित समन्वय साक्ष्य-आधारित निगरानी में योगदान देता है। इसके अतिरिक्त, अनुकूलित डैशबोर्ड तक पहुंच प्रदान करने वाले लॉगिन क्रेडेंशियल पहले ही सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ साझा किए जा चुके हैं, जिससे उन्हें परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए पोर्टल तक सीधी पहुंच प्राप्त हो जाती है।

*****